

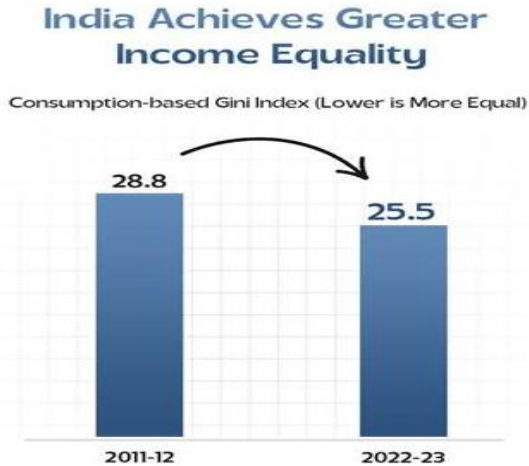


Daily करेंट अफेयर्स

» 31 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. विश्व बैंक की 2025 रिपोर्ट में 25.5 गिनी सूचकांक के साथ भारत आय समानता में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है।



विश्व बैंक स्प्रिंग 2025 गरीबी और इक्विटी ब्रीफ में, विश्व बैंक (WB) ने बताया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 25.5 का गिनी सूचकांक हासिल किया, जिससे वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे समान देश का स्थान प्राप्त हुआ, जो स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस से थोड़ा पीछे है, जिनके असमानता स्कोर क्रमशः 24.1, 24.3 और 24.4 हैं।

● गिनी सूचकांक, जिसे गिनी गुणांक भी कहा जाता है, 1912 में इतालवी सांख्यिकीविद् कोराडो गिनी द्वारा तैयार किया गया एक सांख्यिकीय माप है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या के भीतर आय या धन असमानता का आकलन करना है। यह मीट्रिक 0 (पूर्ण समानता दर्शाता है) से 100 (पूर्ण असमानता दर्शाता है) तक होता है। कम गिनी मान परिवारों या व्यक्तियों के बीच आय के अधिक समान वितरण को दर्शाता है।

● भारत का 25.5 का गिनी स्कोर इसे रिपोर्ट में शामिल 167 देशों में "मध्यम रूप से कम असमानता" श्रेणी में रखता है। देश ने चीन (35.7), अमेरिका (41.8), यूनाइटेड किंगडम (34.4), और जर्मनी (~31.4) सहित सभी G7 और G20 अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे

भारत उन कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया जहाँ असमानता का स्तर इतना कम है।

● भारत के बेहतर गिनी सूचकांक का एक प्रमुख कारण तेज़ी से गरीबी में कमी रही है। 2011 और 2023 के बीच, लगभग 17.1 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले, जिसे 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की वैश्विक सीमा द्वारा परिभाषित किया गया है। इस स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की हिस्सेदारी 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में केवल 2.3% रह गई; 3.00 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की अद्यतन सीमा के तहत, यह दर 5.3% थी।

Key Points:-

(i) इक्विटी में भारत की प्रगति को प्रमुख योजनाओं का समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने वित्तीय समावेशन और कल्याणकारी पहुंच का विस्तार किया है - विशेष रूप से प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), जिसने 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले, आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली ने लगभग 3.48 लाख करोड़ रुपये की लीकेज को बचाया, और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्यक्रम ने 410 मिलियन से अधिक स्वास्थ्य कार्डों को कवर किया, जिसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवर है।

(ii) सराहनीय उपलब्धियों के बावजूद, भारत निरंतर संरचनात्मक असमानता के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। बाहरी आकलनों के अनुसार, शीर्ष 1% लोगों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि जनसांख्यिकीय अंतर—जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और डिजिटल बुनियादी ढाँचे तक असमान पहुँच—दीर्घकालिक आय परिणामों को प्रभावित करते रहते हैं। नीति निर्माताओं से समावेशी सेवाओं और कराधान ढाँचों को और मज़बूत करने का आग्रह किया जाता है।

(iii) वैश्विक आय समानता में भारत का चौथा स्थान एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, खासकर एक विशाल

और विविध राष्ट्र के लिए। 2011-12 में 28.8 के गिनी सूचकांक से 2022-23 में 25.5 तक का सुधार इसकी गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समता नीतियों की सफलता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हुए, समता में किसी भी विपरीत गिरावट को रोकने के लिए समावेशी विकास, लक्षित सामाजिक कल्याण नीतियों और अवसरों की कमी को पाटने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

2. MS धोनी जुलाई 2025 में ACKO के रणनीतिक निवेशक और ब्रांड एंबेसडर बनेंगे।



जुलाई 2025 में, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक प्रमुख डिजिटल बीमा कंपनी, ACKO टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की। धोनी अपने पारिवारिक कार्यालय, मिडास डील्स प्राइवेट लिमिटेड, जो बैंगलोर, कर्नाटक में स्थित है, के माध्यम से एक रणनीतिक निवेशक और ब्रांड एंबेसडर दोनों के रूप में इस फर्म में शामिल हुए हैं।

• MS धोनी ने ACKO के साथ दोहरी भूमिका निभाई है—एक ब्रांड एंबेसडर और एक रणनीतिक निवेशक के रूप में। उनका जुड़ाव मिडास डील्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके पारिवारिक निवेश कार्यालय के माध्यम से है, जो प्रचार संबंधी

ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ एक व्यावसायिक प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

• यह साझेदारी धोनी और ACKO के बीच प्रौद्योगिकी-प्रथम मॉडल का उपयोग करके बीमा क्षेत्र को आधुनिक बनाने के साझा लक्ष्य पर ज़ोर देती है। इसका उद्देश्य डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए बीमा को सरल, अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाकर उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना है।

Key Points:-

(i) धोनी की विश्वसनीयता और व्यापक जनविश्वास के साथ, ACKO भारत की सबसे विश्वसनीय डिजिटल बीमा कंपनी के रूप में अपनी स्थिति मज़बूत करना चाहता है। उनके इस सहयोग से ग्राहकों का विश्वास मज़बूत होने और प्रतिस्पर्धी बाज़ार में ब्रांड की पहचान मज़बूत होने की उम्मीद है।

(ii) यह सहयोग विशेष रूप से शहरी भारतीय ग्राहकों को व्यक्तिगत, तकनीक-सक्षम बीमा उत्पाद प्रदान करके लक्षित करता है। ACKO की योजना इस क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को गति देने की है, साथ ही प्रभावशाली और स्केलेबल नवाचारों में धोनी के विश्वास के अनुरूप भी।

3. महाराष्ट्र ने भारत रत्न डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की शताब्दी वर्ष पर उनके सम्मान में 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में घोषित किया।



29 जुलाई, 2025 को, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि भारत की हरित क्रांति के जनक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के सम्मान में, 7 अगस्त को हर साल सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह पहल उनकी शताब्दी जयंती समारोह का एक प्रमुख हिस्सा है, जो भारतीय कृषि में उनके ऐतिहासिक योगदान को मान्यता प्रदान करता है।

- 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा 29 जुलाई, 2025 को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था, जो कृषि अनुसंधान, खाद्य सुरक्षा और जलवायु-लचीली खेती में डॉ. स्वामीनाथन की स्थायी विरासत को श्रद्धांजलि देने के राज्य स्तरीय प्रयासों का हिस्सा था।

- यह घोषणापत्र 7 अगस्त, 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की 100वीं जयंती (शताब्दी) के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। वर्ष भर चलने वाले ये समारोह हरित क्रांति के दौर में भारत के कृषि परिदृश्य को बदलने में उनके अग्रणी कार्यों को उजागर करते हैं।

- महाराष्ट्र के सभी कृषि विश्वविद्यालयों को डॉ. एमएस स्वामीनाथन जैव-सुख अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। ये केंद्र टिकाऊ कृषि पद्धतियों, जलवायु अनुकूलन तकनीकों और विज्ञान-आधारित कृषि विधियों के

माध्यम से खाद्य सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

Key Points:-

(i) नव घोषित दिवस के उपलक्ष्य में, महाराष्ट्र सरकार टिकाऊ और जलवायु-स्मार्ट कृषि के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी स्मारक कार्यक्रम, कृषि-केंद्रित पुरस्कार, किसान नवाचार प्रदर्शन और समुदाय-आधारित आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेगी।

(ii) डॉ. स्वामीनाथन को गेहूँ और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYV) को विकसित करने के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है, जिससे 1960-70 के दशक में भारत में खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिन्होंने देश की खाद्य आत्मनिर्भरता की नींव रखी।

(iii) राष्ट्र के प्रति उनकी अभूतपूर्व सेवा के सम्मान में, डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन को मरणोपरान्त वर्ष 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इससे भारत के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों और सार्वजनिक हस्तियों में उनका स्थान और भी मज़बूत हो गया।

INTERNATIONAL

1. डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस के साथ संबंधों को लेकर भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने की घोषणा की है, जो 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगा।



30 जुलाई, 2025 को, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के खिलाफ एक व्यापक व्यापारिक कार्रवाई की घोषणा की: भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ और रूस के साथ भारत के सैन्य और ऊर्जा संबंधों से जुड़ा एक अतिरिक्त अनिर्दिष्ट जुर्माना। ये उपाय, जो 1 अगस्त से प्रभावी होंगे, यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत की व्यापार बाधाओं और मास्को के साथ रणनीतिक गठबंधन से जुड़ी शिकायतों से उपजे हैं।

- ट्रम्प ने अपने ट्विटर सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घोषणा की कि 1 अगस्त, 2025 से अमेरिका को सभी भारतीय निर्यातों पर 25% टैरिफ लगेगा, साथ ही रूस के साथ भारत के संबंधों से संबंधित एक अतिरिक्त "जुर्माना" भी लगेगा।

- ट्रम्प ने भारत के "उच्च टैरिफ" और "कठोर और अप्रिय गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाओं" का हवाला देते हुए इस कदम को उचित ठहराया, जिनके बारे में उनका दावा है कि उनकी कथित मित्रता के बावजूद, इनके कारण अमेरिका-भारत व्यापार सीमित हो गया है।

- दंड का मुख्य औचित्य भारत द्वारा रूसी सैन्य उपकरणों और ऊर्जा की निरंतर खरीद से जुड़ा है, जिसके बारे में ट्रम्प का तर्क है कि यह यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों का समर्थन करता है और वैश्विक प्रतिबंधों को कमजोर करता है।

Key Points:-

(i) भारत ने 2024 में अमेरिका को लगभग 86-128 अरब डॉलर का माल निर्यात किया, जिससे अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया। जिन क्षेत्रों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका है, उनमें वस्त्र, दवाइयाँ, रत्न, आभूषण, पेट्रोकेमिकल और मशीनरी शामिल हैं।

(ii) 2030 तक व्यापार को दोगुना करके 500 अरब डॉलर तक पहुँचाने के उद्देश्य से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत के बावजूद, भारत और अमेरिका ट्रम्प की 1 अगस्त की समय सीमा से पहले कोई समझौता करने में विफल रहे। ट्रम्प ने संकेत दिया कि वे उन देशों पर टैरिफ लगाएँगे जो समझौते को अंतिम रूप नहीं देंगे।

(iii) इस फैसले से यूक्रेन युद्ध के बीच भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। भारत ने तब से रूसी तेल की खरीदारी रोक दी है, और सरकारी तेल शोधक दबाव में आपूर्तिकर्ता बदल रहे हैं। इस बीच, ट्रंप ने पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय साझेदारों के साथ अमेरिकी संबंधों को गहरा किया है, जिससे रणनीतिक झुकाव को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

2. ऑस्ट्रेलिया ने 10 दिसंबर, 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए YouTube पर प्रतिबंध लगा दिया है।



ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन अधिनियम 2024 के तहत, 10 दिसंबर, 2025 से प्रभावी, 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म की सूची में YouTube को आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया है। इस कदम का उद्देश्य बच्चों के लिए हानिकारक ऑनलाइन सामग्री के विरुद्ध सुरक्षा को मज़बूत करना है।

- YouTube को शुरुआत में छूट दी गई थी, लेकिन हाल ही में ई-सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट द्वारा नाबालिगों के हिंसक और हानिकारक सामग्री के संपर्क में आने के बढ़ते मामलों का हवाला देने के बाद इसे शामिल किया गया। अब इस प्लेटफॉर्म को कानून के तहत एक सोशल मीडिया साइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- 2024 के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चला है कि 37% बच्चों ने YouTube पर परेशान करने वाली सामग्री का सामना करने की सूचना दी है, जो सभी प्लेटफॉर्म में सबसे अधिक है। इसमें षड्यंत्र के सिद्धांत, स्त्री द्वेष, हिंसा और आत्म-क्षति पहुँचाने वाली सामग्री का संपर्क शामिल था।

Key Points:-

(i) नए नियमों के तहत, YouTube सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नाबालिगों के अकाउंट हटाने होंगे, नए अकाउंट बनाने से रोकना होगा और सख्त आयु-सत्यापन तंत्र लागू करना होगा। ऐसा न करने वाली कंपनियों पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है।

(ii) बच्चे अब भी बिना साइन इन किए YouTube पर सार्वजनिक वीडियो देख पाएँगे, लेकिन लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब करने जैसी सुविधाएँ उम्र की पुष्टि होने तक प्रतिबंधित रहेंगी।

(iii) इस फैसले का प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने समर्थन किया है, जबकि YouTube की मूल कंपनी, अल्फाबेट इंक. ने इस कदम का विरोध किया है। उनका कहना है कि YouTube एक सामान्य सोशल

मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है और वे इस कानून को चुनौती दे सकते हैं।

3. रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद क्लुचेव्स्कोय ज्वालामुखी फट गया।



30 जुलाई, 2025 को, रूस का क्लुचेव्स्कोय ज्वालामुखी—यूरेशिया के सबसे ऊँचे और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी—कामचटका प्रायद्वीप पर नाटकीय रूप से फट गया, तट पर 8.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कुछ ही घंटों बाद। इस प्राकृतिक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया ने ज्वालामुखी विस्फोट, राख के गुबार, लावा प्रवाह और पूरे क्षेत्र में भूकंपीय चेतवनी प्रतिक्रिया को जन्म दिया।

- कामचटका के तट से लगभग 119 किलोमीटर दूर, लगभग 19 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया यह भूकंप 1952 के बाद से इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली भूकंप है, और इसके कारण प्रशांत महासागर के सभी हिस्सों में व्यापक सुनामी की चेतावनी जारी की गई - जिसमें जापान, हवाई, इक्वाडोर और चिली भी शामिल हैं। हालाँकि इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं और कई लोग घायल हुए, लेकिन मज़बूत बुनियादी ढाँचे और त्वरित निकासी की बदौलत कोई हताहत नहीं हुआ।

- भूकंप के झटके महसूस होते ही क्लुचेव्स्कोय ज्वालामुखी फट गया, जिसके शिखर पर

शक्तिशाली चमक, विस्फोटक विस्फोट और उसके पश्चिमी किनारे पर लावा का दृश्य दिखाई दिया, जिसकी पुष्टि रूसी विज्ञान अकादमी की संयुक्त भूभौतिकीय सेवा ने टेलीग्राम के माध्यम से की।

● विस्फोट से राख का एक विशाल गुबार आसमान में 3 किमी (1.5 मील) से भी ऊपर उठकर पूर्व की ओर 60 किमी तक फैल गया। इससे विमानन सुरक्षा जोखिम का स्तर बढ़ गया—कामचटका के आसपास के क्षेत्र में उड़ानों के लिए कॉकपिट चेतावनियाँ और हवाई क्षेत्र की निगरानी जारी कर दी गई।

Key Points:-

(i) 4,754 मीटर की ऊँचाई पर स्थित क्लुचेव्स्कॉय को दुनिया के सबसे अस्थिर ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। हाल ही में की गई निगरानी ने जुलाई के मध्य में ही तापीय विसंगतियों की पहचान कर ली थी, और मई के अंत तक शिखर से 1.7 किमी ऊपर तक राख उत्सर्जन दर्ज किया गया था। इन्हें नारंगी स्तर की चेतावनी दी गई थी, जो विस्फोट से पहले के दिनों में बढ़े हुए जोखिम का संकेत था।

(ii) हालाँकि यह विस्फोट एक विरल आबादी वाले क्षेत्र में हुआ था, फिर भी इसने भूकंप से उबरने के प्रयासों को और जटिल बना दिया। सेवेरो-कुरिल्स्क में 4-5 मीटर ऊँची सुनामी लहरों के साथ, जिससे बाढ़ और बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा, इस घटना ने रूस की भूकंपीय-भूवैज्ञानिक संकटों के प्रति संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया।

BANKING & FINANCE

1. SEBI और स्टॉक एक्सचेंजों ने ₹1,000 करोड़ से कम बाजार पूंजीकरण वाली छोटी-कैप फर्मों के लिए उन्नत निगरानी तंत्र को संशोधित किया।



25 जुलाई, 2025 को, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (MSEI) के साथ मिलकर उन्नत निगरानी तंत्र (ESM) ढाँचे में बड़े बदलावों की घोषणा की। इन बदलावों का उद्देश्य खुदरा निवेशकों की सुरक्षा के साथ-साथ स्मॉल-कैप फर्मों के वास्तविक विकास को बढ़ावा देना है और ये 28 जुलाई, 2025 से प्रभावी होंगे।

● संशोधित ढाँचा तब पेश किया गया जब सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों ने पाया कि कई बुनियादी रूप से मज़बूत स्मॉल-कैप कंपनियों को पुरानी प्रणाली के तहत गलत तरीके से चिह्नित किया जा रहा था। इस समस्या से निपटने के लिए, मौजूदा निगरानी तंत्र में मूल्यांकन-आधारित मानदंड जोड़े गए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मज़बूत वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों पर अनावश्यक प्रतिबंध न लगाए जाएँ। इस अद्यतन का मुख्य उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा और भारत के पूंजी बाजार में विकास के अवसरों के बीच संतुलन बनाना है।

● संशोधित मानदंडों के तहत, अब किसी भी कंपनी को चरण I से चरण II निगरानी में तभी स्थानांतरित किया जा सकता है जब वह कड़े मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करती हो। विशेष रूप से, कंपनियों को चिह्नित किया जाएगा यदि उनका मूल्य-से-आय (पीई) अनुपात शून्य या ऋणात्मक (घाटे का संकेत)

है, या यदि यह निफ्टी 500 सूचकांक के पीई के दोगुने से अधिक है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल अधिक मूल्यांकित या घाटे में चल रही कंपनियों पर ही कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, न कि हर अस्थिर शेयर पर।

● चरण 1 में शामिल होने के लिए, कंपनियों को अब 3, 6, या 12 महीनों में असामान्य मूल्य अस्थिरता के साथ-साथ पिछले तीन महीनों में बढ़ती कीमतों का रुझान भी प्रदर्शित करना होगा। इसके अलावा, शेयर में अपने स्मॉल-कैप समकक्षों की तुलना में अस्थिरता में 1 मानक विचलन से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि केवल स्पष्ट सट्टा गति वाले शेयरों को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

Key Points:-

(i) SEBI (भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड) के उन्नत निगरानी तंत्र (ESM) के पहले चरण में, अगर स्मॉल-कैप कंपनियों के शेयरों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, तो उन पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। उन्हें टी+2 दिन (ट्रेड के दो दिन बाद) से 100% मार्जिन नियमों का पालन करना होगा, प्रत्येक ट्रेड का निपटान व्यक्तिगत रूप से (ट्रेड-फॉर-ट्रेड) किया जाएगा, और मूल्य परिवर्तन सीमा को घटाकर $\pm 5\%$ या $\pm 2\%$ कर दिया जाएगा। दूसरे चरण में जाने के लिए, कंपनी के शेयर में 5 दिनों में 15% या एक महीने में 30% की वृद्धि होनी चाहिए, और इसका मूल्यांकन (PE अनुपात की तरह) भी उँचा होना चाहिए, जो संभावित मूल्य हेरफेर या अधिक मूल्य निर्धारण का संकेत देता है।

(ii) निगरानी ढाँचे का चरण II उच्चतम स्तर के प्रतिबंध लागू करता है, जहाँ व्यापार केवल आवधिक कॉल नीलामी के माध्यम से ही संभव है और मूल्य परिवर्तन को $\pm 2\%$ की सख्त सीमा पर रखा गया है। ये उपाय सट्टा गतिविधियों को धीमा करने के साथ-साथ अत्यधिक अस्थिरता और खराब मूल्यांकन वाले स्मॉल-कैप शेयरों के लिए व्यवस्थित मूल्य निर्धारण

सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

(iii) SEBI द्वारा 28 जुलाई, 2025 को शुरू किए गए इस संशोधित ESM ढाँचे से वर्तमान में निगरानी में रह रही 28 कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अगस्त 2023 में पहली बार ₹1,000 करोड़ से कम बाज़ार पूंजीकरण वाली कंपनियों के लिए लागू किए गए इस नवीनतम अपडेट में पीई अनुपात जैसे मूल्यांकन-आधारित फ़िल्टर शामिल किए गए हैं ताकि वास्तविक स्मॉल-कैप ग्रोथ स्टॉक्स को सट्टा स्टॉक्स से अलग किया जा सके।

2. RBI ने वैकल्पिक निवेश फंड्स (AIFs) में विनियमित संस्थाओं के निवेश के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे



जुलाई 2025 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने RBI (वैकल्पिक निवेश फंड्स में निवेश) दिशा-निर्देश, 2025 जारी किए, जिसमें बैंकों और NBFC जैसी विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities – REs) द्वारा वैकल्पिक निवेश फंड्स (Alternative Investment Funds – AIFs) में निवेश पर सख्त सीमाएं निर्धारित की गई हैं। ये नए दिशा-निर्देश 1 जनवरी 2026 से प्रभाव में आएंगे, हालांकि संस्थाएं स्वेच्छा से इन्हें पहले भी लागू कर सकती हैं।

● इस नए ढाँचे का उद्देश्य एक ही AIF स्कीम में वित्तीय प्रणाली के अत्यधिक निवेश को रोकना है।

इसके तहत किसी भी विनियमित संस्था (RE) द्वारा किसी AIF स्कीम के कुल कोष (कॉर्पस) का अधिकतम 20% तक ही निवेश करने की अनुमति होगी। यह दिशानिर्देश RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में उन चिंताओं के जवाब में जारी किए गए हैं जो AIF के माध्यम से अप्रत्यक्ष ऋण जोखिम से जुड़ी हैं।

- ये दिशा-निर्देश वाणिज्यिक बैंक (Scheduled Commercial Banks – SCBs), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks – RRBs), लोकल एरिया बैंक (Local Area Banks – LABs), स्मॉल फाइनेंस बैंक (Small Finance Banks – SFBs), सहकारी बैंक (Urban, State और Central Co-operative Banks), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (Non-Banking Financial Companies – NBFCs) जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (HFCs) भी शामिल हैं, और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (All-India Financial Institutions – AIFIs) जैसे नाबार्ड (NABARD), भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank), SIDBI और राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) पर लागू होंगे।

- नए नियमों के अनुसार, कोई भी एकल विनियमित संस्था किसी एक AIF स्कीम के कुल कॉर्पस का 10% से अधिक निवेश नहीं कर सकती। साथ ही, सभी विनियमित संस्थाएं मिलकर किसी एक AIF स्कीम में 20% से अधिक का योगदान नहीं कर सकतीं। इस सीमा का उद्देश्य जोखिम को केंद्रित होने से रोकना है और बाजार में विविधता बनाए रखना है।

Key Points:-

(i) नए निर्देशों में सख्त प्रावधान आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है। यदि कोई विनियमित संस्था किसी AIF में 5% से अधिक निवेश करती है और वही AIF उस संस्था के कर्जदारों की कंपनियों (debtor companies) में निवेश करता है (केवल

इकिटी को छोड़कर), तो उस स्थिति में संस्था को उस निवेश के बराबर 100% प्रावधान (provisioning) करना होगा। यह प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से जोखिमपूर्ण कंपनियों को वित्तीय सहायता देने से रोकने के लिए है।

(ii) RBI ने इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए 1 जनवरी 2026 तक का समय दिया है ताकि सभी संस्थाएं अपने निवेश को नए ढांचे के अनुसार समायोजित कर सकें। हालांकि, संस्थाएं चाहें तो स्वेच्छा से इन नियमों को पहले भी लागू कर सकती हैं। इससे निवेश व्यवहार में सावधानी आएगी और वित्तीय क्षेत्र में जुड़ाव को संतुलित किया जा सकेगा।

(iii) यह नीति सुधार छाया बैंकिंग (shadow banking) और निवेश फंड क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में RBI के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय स्थिरता के उद्देश्यों से भी मेल खाता है, जिसके प्रमुख केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं।

MOUs and Agreement

1. भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



30 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) की बैठक के दौरान,

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) और संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय रक्षक कमान (UAE NGC) ने समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए। यह आयोजन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मज़बूत करने में एक रणनीतिक मील का पत्थर है।

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने समझौता ज्ञापन के तहत तटरक्षक बल के प्रमुख कार्यों में संयुक्त प्रयासों को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इनमें समुद्री खोज एवं बचाव (M-SAR), अंतरराष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटना, समुद्री कानून प्रवर्तन (MLE), समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया (MPR), और संयुक्त क्षमता निर्माण अभ्यास शामिल हैं।

- यह समझौता ज्ञापन भारत द्वारा मित्र देशों के तट रक्षकों के साथ हस्ताक्षरित दसवाँ ऐसा समझौता है। यह भारत के रणनीतिक सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और सतत महासागरीय शासन को बढ़ावा देना है।

Key Points:-

(i) यह समझौता भारत-UAE रक्षा सहयोग को भी आगे बढ़ाता है, जिसमें वास्तविक समय में समुद्री सूचना साझा करने, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और UAE की ज़रूरतों के अनुरूप सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विस्तारित सहयोग शामिल है। जेडीसीसी में, भारत ने UAE सशस्त्र बलों को अनुकूलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने की भी प्रतिबद्धता जताई।

(ii) इससे पहले 2025 में, भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत ICGS शूर ने NAVDEX/IDEX 2025 में भाग लेने के लिए अबू धाबी में डॉक किया था। सद्भावना यात्रा ने भारत की समुद्री क्षमताओं को प्रदर्शित किया, खोज और बचाव उपकरणों का

प्रदर्शन किया, और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले आमने-सामने की बातचीत की सुविधा प्रदान की।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया, वे 1 सितंबर 2025 से कार्यभार संभालेंगे।



जुलाई 2025 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने वरिष्ठ IPS अधिकारी संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल (SSB) के अगले महानिदेशक (DG) के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल (BSF) में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत सिंघल, 31 अगस्त, 2025 को वर्तमान महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद के सेवानिवृत्त होने के बाद, 1 सितंबर, 2025 से यह पदभार ग्रहण करेंगे।

- कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा एसएसबी के महानिदेशक के रूप में संजय सिंघल की नियुक्ति को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है और वह 1 सितंबर, 2025 को अपना कार्यभार संभालेंगे। वह 31 दिसंबर, 2028 को अपनी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेश तक इस शीर्ष पद पर कार्य करेंगे, जिससे उनका कार्यकाल संभावित रूप से तीन वर्ष से अधिक लंबा हो जाएगा।

- SSB का नेतृत्व संभालने से पहले, सिंघल सीमा सुरक्षा बल (BSF) में विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने राष्ट्रीय सीमा प्रबंधन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एसएसबी में उनकी यह नई नियुक्ति भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के उनके अनुभव का विस्तार है।

- संजय सिंघल भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 1993 बैच के अधिकारी हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश (UP) कैडर आवंटित किया गया है। पिछले तीन दशकों में, उन्होंने नागरिक पुलिस व्यवस्था और अर्धसैनिक बल कमान, दोनों में विशेषज्ञता के साथ एक रणनीतिक नेता के रूप में अपनी ठोस प्रतिष्ठा बनाई है।

Key Points:-

(i) अपने पूरे कार्यकाल में, सिंघल ने राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, दोनों में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। उनके मुख्य अनुभव में 2008 से 2015 तक भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में DIG और फिर IG का पद शामिल है। उत्तर प्रदेश पुलिस में, उन्होंने आईजी, DGP के जनरल स्टाफ ऑफिसर, ADG अपराध, ADG रेलवे और ADG स्थापना के पदों पर कार्य किया है, साथ ही विभिन्न जिलों में SP के रूप में कई PAC बटालियनों का नेतृत्व भी किया है।

(ii) संजय सिंघल का योगदान राष्ट्रीय कर्तव्यों से कहीं आगे तक फैला हुआ है, उन्हें कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में उनकी भूमिका के लिए सम्मान मिला है। उनकी असाधारण सेवा के लिए उन्हें 2009 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और 2015 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।

(iii) गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन कार्यरत सशस्त्र सीमा बल (SSB) को नेपाल और भूटान से लगती भारत की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया

है। आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद-निरोध और सीमा बल नेतृत्व में उनके व्यापक क्षेत्रीय अनुभव के कारण, सिंघल की नियुक्ति को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो सीमा क्षेत्र की सुरक्षा और सद्भाव सुनिश्चित करने के SSB के मिशन के अनुरूप है।

2. भारतीय मूल के टेक कार्यकारी निखिल रविशंकर को एयर न्यूज़ीलैंड का अगला CEO नियुक्त किया गया, जो 20 अक्टूबर 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे।



जुलाई 2025 के अंत में, एयर न्यूज़ीलैंड ने घोषणा की कि निखिल रविशंकर, जो वर्तमान में उसके मुख्य डिजिटल अधिकारी हैं, को एयरलाइन का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति एक वैश्विक खोज के बाद हुई है और ऐसे समय में हुई है जब ग्रेग फ़ोरन अक्टूबर में पद छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे एक नए डिजिटल-केंद्रित नेतृत्व युग की शुरुआत होगी।

- एयर न्यूज़ीलैंड ने 30 जुलाई, 2025 को निखिल रविशंकर को अपना नया CEO नियुक्त किया है। वह 20 अक्टूबर, 2025 को निवर्तमान CEO ग्रेग फ़ोरन का स्थान लेंगे।

- रविशंकर, ग्रेग फ़ोरन का स्थान लेंगे, जिन्होंने लगभग छह वर्षों तक एयरलाइन का नेतृत्व किया और कोविड-19 संकट और परिचालन संबंधी

बाधाओं के दौरान इसकी देखरेख की। नेतृत्व परिवर्तन को एयरलाइन के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

● प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन विशेषज्ञ, रविशंकर 2021 में एयर न्यूज़ीलैंड में मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में शामिल हुए। इससे पहले, उन्होंने वेक्टर न्यूज़ीलैंड और एक्सेंचर (हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में) में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया था, और टेलीकॉम न्यूज़ीलैंड (अब स्पार्क) में प्रौद्योगिकी रणनीति में अपना करियर शुरू किया था।

Key Points:-

(i) अपने लगभग पाँच साल के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने एयरलाइन की तकनीकी रीढ़, लॉयल्टी प्रोग्राम और ग्राहक प्रस्ताव में महत्वपूर्ण प्रगति का नेतृत्व किया। विमानन व्यवसाय की उनकी गहरी समझ को बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण संपत्ति बताया।

(ii) बोर्ड अध्यक्ष डेम थेरेसा वॉल्श ने उनकी नियुक्ति को एयर न्यूज़ीलैंड के लिए अगले अध्याय की शुरुआत बताया और रविशंकर की डिजिटल साक्षरता, वैश्विक दृष्टिकोण, नेतृत्व कौशल और न्यूज़ीलैंड के मूल्यों के साथ उनके जुड़ाव पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि व्यापक विमानन उद्योग गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है—जलवायु परिवर्तन, ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाएँ, लागत का दबाव और भू-राजनीति—ऐसे क्षेत्र जहाँ रविशंकर का नया दृष्टिकोण महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

3. भारत बी. भाटिया को जुलाई 2025 में APT के WRC-27 तैयारी समूह का उपाध्यक्ष और संपादकीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया।



जुलाई 2025 में, ITU-APT फाउंडेशन ऑफ इंडिया (IAFI) के अध्यक्ष, भारत बी. भाटिया को विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2027 (WRC-27), जिसे APG-27 भी कहा जाता है, के लिए एशिया-प्रशांत दूरसंचार (APT) तैयारी समूह का उपाध्यक्ष और संपादकीय समिति अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 28 जुलाई से 1 अगस्त, 2025 तक थाईलैंड के पटायी में आयोजित पूर्ण अधिवेशन के दौरान उनकी नियुक्ति को औपचारिक रूप दिया गया।

● भारत भाटिया को WRC-27 की तैयारी कर रही क्षेत्रीय समन्वय संस्था, APG-27 के उपाध्यक्ष और संपादकीय अध्यक्ष, दोनों के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी दोहरी भूमिका में उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श का मार्गदर्शन और वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम मानकों के लिए क्षेत्रीय योगदान के प्रारूपण की देखरेख शामिल होगी।

● उनके नामांकन का प्रस्ताव एपीजी-27 के अध्यक्ष जापान के नोबुयुकी कवाई ने रखा था, तथा 30 एशिया-प्रशांत देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों ने सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दे दी, जिससे क्षेत्रीय सहमति और उनके नेतृत्व में विश्वास का पता चलता है।

Key Points:-

(i) भारत बी. भाटिया ने संचार मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विभाग (DoT) में दो दशकों से

अधिक समय तक सेवा की है। उन्होंने 1981 में भारत की पहली राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना (NFAP) के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1992 में देश के पहले GSM नेटवर्क की शुरुआत का नेतृत्व किया।

(ii) भारतीय रेडियो नियामक सेवा (IRRS) के 22 वर्षों के अनुभवी के रूप में, भरत भाटिया ने भारत की राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम नीति और नियामक संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वे भारत के दूरसंचार और वायरलेस शासन पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए।

(iii) क्षेत्रीय जिम्मेदारियों के अलावा, भाटिया अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) कार्य समूह के अध्यक्ष भी हैं, जिसका कार्य वैश्विक IMT (अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार) मानकों को तैयार करना है, जिसमें 5G और आगामी 6G नेटवर्क के लिए मानक भी शामिल हैं। एपीजी-27 में उनकी नियुक्ति वैश्विक स्पेक्ट्रम और मोबाइल प्रौद्योगिकी नीति पर उनके प्रभाव को और पुष्ट करती है।

SPORTS

1. भारतीय हॉकी के 100 वर्ष: हॉकी इंडिया ने बढ़ी हुई अनुदान राशि और राष्ट्रव्यापी महोत्सव की घोषणा की।



भारतीय हॉकी के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय और जमीनी स्तर के टूर्नामेंटों के लिए बढ़े हुए वित्तीय अनुदान के एक ऐतिहासिक पैकेज का अनावरण किया और 27 जुलाई, 2025 को महाबलीपुरम में आयोजित अपनी 15वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान 7 नवंबर, 2025 को एक भव्य राष्ट्रव्यापी हॉकी महोत्सव की घोषणा की।

● **हॉकी इंडिया ने अपने वित्त पोषण आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है:** अब सीनियर पुरुष और सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए ₹70-₹70 लाख, और जूनियर पुरुष, जूनियर महिला, सब-जूनियर पुरुष और सब-जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए ₹30-₹30 लाख दिए जाएंगे। इन बढ़े हुए अनुदानों का उद्देश्य प्रतियोगिता की गुणवत्ता को मज़बूत करना और राष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना है।

● **जमीनी स्तर पर प्रतिभा विकास को मज़बूत करने के लिए,** प्रत्येक राज्य संघ को ज़िला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए सालाना ₹25 लाख मिलेंगे। इस स्थिर धनराशि का उद्देश्य संगठनात्मक लागत को कम करना, व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देना और पूरे भारत में विविध हॉकी प्रतिभाओं को विकसित करना है।

Key Points:-

(i) शताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में, हॉकी इंडिया 7 नवंबर, 2025 को एक राष्ट्रव्यापी उत्सव का आयोजन करेगा, जिसमें 1,000 मैच एक साथ होंगे— प्रत्येक जिले में एक पुरुष और एक महिला मैच। इस आयोजन में 36,000 से अधिक खिलाड़ियों (18,000 पुरुष और 18,000 महिला) के भाग लेने की उम्मीद है, जो लैंगिक संतुलन और राष्ट्रव्यापी समावेशिता दोनों को दर्शाता है।

(ii) हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिकी ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल भारत की गौरवशाली हॉकी विरासत का सम्मान करती है, साथ ही इसके

भविष्य में रणनीतिक निवेश भी करती है: उन्होंने कहा, "ये अनुदान अगली पीढ़ी के सपनों में प्रत्यक्ष निवेश हैं", उन्होंने उत्सव और विकास के दोहरे लक्ष्य पर प्रकाश डाला ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि "संसाधनों की कमी के कारण कोई प्रतिभा पीछे न छूट जाए।"

(iii) यह ऐतिहासिक कदम विरासत और दूरदर्शिता का सम्मिश्रण है—जो राष्ट्रीय एकता और खेल महत्वाकांक्षा का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। इस वित्तीय सहायता में वृद्धि और नवंबर में होने वाले विशाल उत्सव से स्थानीय संघों में ऊर्जा का संचार होने, उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलने और भारत के खेल गौरव के प्रतीक के रूप में हॉकी की भूमिका को और मज़बूत करने की उम्मीद है।

2. AIFF ने भारतीय फुटबॉल बिरादरी के समर्थन के लिए 'परोपकार निधि' की शुरुआत की और 'पेंशन निधि' का प्रस्ताव रखा।



जुलाई 2025 में, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने दो कल्याणकारी पहलों की शुरुआत की - 'परोपकार निधि' और एक प्रस्तावित 'पेंशन निधि' - जिसका उद्देश्य भारतीय फुटबॉल से जुड़े सेवानिवृत्त खिलाड़ियों, कोचों, रेफरी, अधिकारियों और कर्मचारियों का समर्थन करना है।

- ये निर्णय नई दिल्ली में आयोजित AIFF की कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान लिए गए।

- 'परोपकार निधि' की स्थापना खिलाड़ियों और रेफरी सहित भारतीय फुटबॉल समुदाय के सेवानिवृत्त सदस्यों को एकमुश्त चिकित्सा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान सहायता प्राप्त हो।

- यह कोष 7,00,002 रुपये की राशि से शुरू होता है, जिसमें से AIFF अध्यक्ष कल्याण चौबे और उपाध्यक्ष एन. ए. हारिस ने व्यक्तिगत रूप से 1,00,001 रुपये का योगदान दिया, जो खिलाड़ियों के कल्याण के लिए मजबूत नेतृत्व समर्थन को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) एक विशेष समिति परोपकार निधि की देखरेख करेगी, जिसके पास आवेदकों की योग्यता और वित्तीय या चिकित्सा आवश्यकताओं के आधार पर आवेदनों की समीक्षा करने और उन्हें अनुमोदित करने का अधिकार होगा।

(ii) AIFF ने अपने लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के लिए 'पेंशन फंड' के विचार को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए पात्रता के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा और 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु में सेवानिवृत्ति की आवश्यकता होगी।

(iii) हालांकि पेंशन फंड प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसका क्रियान्वयन तभी शुरू होगा जब नामित समितियों द्वारा परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जिससे AIFF कर्मचारियों के लिए संरचित सेवानिवृत्ति सहायता सुनिश्चित हो सकेगी।

3. विश्व एथलेटिक्स ने 1 सितंबर, 2025 से महिला श्रेणी की पात्रता के लिए अनिवार्य जीन परीक्षण लागू किया।



23 जुलाई, 2025 को, विश्व एथलेटिक्स परिषद ने नए पात्रता नियमों को मंजूरी दी, जिसके तहत विश्व चैंपियनशिप जैसी विशिष्ट विश्व-रैंकिंग प्रतियोगिताओं में महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने की इच्छुक सभी एथलीटों को एक बार SRY जीन परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा। ये नए नियम 13-21 सितंबर को होने वाली टोक्यो विश्व चैंपियनशिप से पहले, 1 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगे।

- नए नियमों के तहत, एथलीटों को SRY जीन की उपस्थिति या अनुपस्थिति की पुष्टि के लिए गाल के स्वाब या सूखे रक्त के धब्बे के परीक्षण द्वारा एक बार आनुवंशिक जाँच करवानी होगी, जो पुरुषों के जैविक लक्षणों का निर्धारण करता है। यह परीक्षण विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में महिला वर्ग की सभी प्रतियोगियों के लिए अनिवार्य है और इसका प्रबंधन प्रत्येक एथलीट के राष्ट्रीय महासंघ द्वारा किया जाएगा।

- विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए ने जोर देकर कहा कि इस नीति का उद्देश्य महिला खेलों में निष्पक्षता की रक्षा करना है: "उच्च स्तर पर... आपको जैविक रूप से महिला होना ज़रूरी है," और कहा कि "लिंग जैविक रूप से महिला नहीं हो सकता"। इन नियमों का उद्देश्य उन जैविक

प्रदर्शन लाभों को संबोधित करना है जो वर्तमान टेस्टोस्टेरोन-कम करने वाले नियमों द्वारा कम नहीं किए जा सकते।

- यह नियामक बदलाव 2018 और 2023 में लागू किए गए पूर्व पात्रता ढाँचों पर आधारित है, जिनके अनुसार पुरुष यौवन प्राप्त करने वाली ट्रांसजेंडर महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा जाना चाहिए और लिंग विकास में अंतर (DSD) वाले एथलीटों को कम से कम छह महीने तक चिकित्सकीय रूप से टेस्टोस्टेरोन का स्तर 2.5nmol/L से कम रखना होगा। एक कार्य समूह ने इन नियमों में कमियों की पहचान की और एकीकृत मानदंडों के तहत DSD और ट्रांसजेंडर दिशानिर्देशों को संयोजित करने की सिफारिश की।

Key Points:-

(i) 10 फरवरी से 5 मार्च, 2025 के बीच, विश्व एथलेटिक्स ने सदस्य महासंघों, एथलीटों और विशेषज्ञों से प्रतिक्रिया आमंत्रित की। कार्य समूह ने पाँच प्रमुख उपायों की सिफारिश की, जिनमें सभी महिला-श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए पूर्व-मंजूरी परीक्षण और महिला श्रेणी परिभाषाओं का औपचारिक सत्यापन शामिल है। परामर्श प्राप्त अधिकांश हितधारकों ने नीति को वैज्ञानिक निष्कर्षों के अनुरूप बनाने के लिए इन सुधारों का समर्थन किया।

(ii) यह कदम कैस्टर सेमेन्या जैसे उच्च-प्रोफ़ाइल एथलीटों से संबंधित चल रही कानूनी जांच के बाद उठाया गया है, जिनकी DSD नियमों के संबंध में अपील यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी।

(iii) मुक्केबाज़ी में भी इसी तरह के आनुवंशिक परीक्षण उपाय अपनाए गए हैं, और व्यापक खेल संस्थाएँ पात्रता सुधारों का मूल्यांकन कर रही हैं। विश्व एथलेटिक्स का यह निर्णय उसे ऐसे नियम लागू करने वाले पहले महासंघों में शामिल करता है।

OBITUARY

1. पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और IDBI बैंक के अध्यक्ष टी. एन. मनोहरन का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया।



पद्मश्री से सम्मानित और IDBI (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) के अध्यक्ष, वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट टी. एन. मनोहरन का 30 जुलाई, 2025 को मुंबई में निधन हो गया। 7 अप्रैल, 1956 को तमिलनाडु में जन्मे मनोहरन ने भारत के वित्तीय, लेखा परीक्षा और बैंकिंग सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे ICAI (भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान) के पूर्व अध्यक्ष और हजारों CA (चार्टर्ड अकाउंटेंट) उम्मीदवारों के मार्गदर्शक भी थे।

● मनोहरन ने वाणिज्य में स्नातकोत्तर और कानून की डिग्री हासिल की और 1983 में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में योग्यता प्राप्त की। उन्होंने मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स नामक एक प्रमुख CA फर्म की स्थापना की और सीए बनने के इच्छुक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की।

● वे 2001 से ICAI की केंद्रीय परिषद के सदस्य रहे और 2006-07 के कार्यकाल के लिए ICAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने 2009 से 2011 तक CII (भारतीय उद्योग परिसंघ) की लेखा मानक एवं कराधान समिति के अध्यक्ष रहे। इसके अतिरिक्त, वे RBI

(भारतीय रिज़र्व बैंक), SEBI (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड), CVC (केंद्रीय सतर्कता आयोग), CAG (भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक), और CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) जैसी संस्थाओं के अंतर्गत विशेषज्ञ समितियों के सदस्य भी रहे।

● 2009 में, उन्हें सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के सरकार द्वारा नामित बोर्ड में नियुक्त किया गया, जिससे कंपनी को उस समय के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के बाद पुनर्जीवित करने में मदद मिली। इस बदलाव में उनकी भूमिका का वर्णन बाद में उनकी पुस्तक "टेक फीनिक्स: सत्यम 100-डे टर्नअराउंड" में किया गया।

Key Points:-

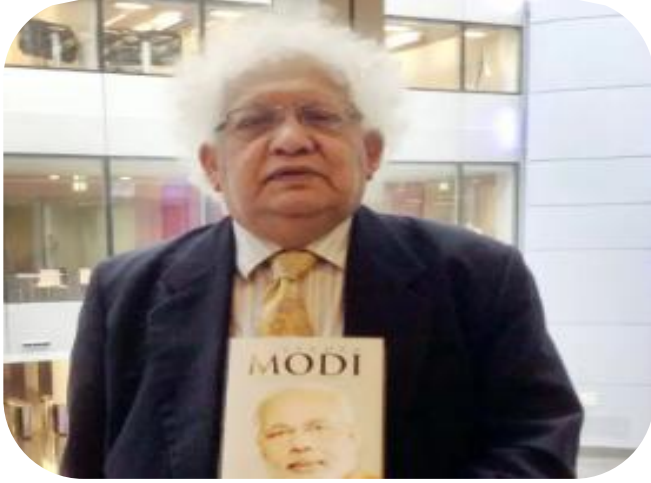
(i) मनोहरन अगस्त 2020 तक केनरा बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष रहे। उन्होंने लक्ष्मी विलास बैंक के प्रशासक के रूप में भी कार्य किया और डीबीएस (डेवलपमेंट बैंक ऑफ़ सिंगापुर) बैंक के साथ इसके विलय की देखरेख की। वे भारत सरकार द्वारा स्थापित विकास वित्तीय संस्थान, NaBFID (नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट) के बोर्ड सदस्य भी थे।

(ii) मई 2022 में, उन्हें तीन साल के कार्यकाल के लिए IDBI (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवधि के दौरान, उन्होंने शासन सुधारों को लागू करने, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और बैंक की वित्तीय रणनीति एवं संचालन का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(iii) टी. एन. मनोहरन को अप्रैल 2010 में व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा पद्म श्री (भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार) से सम्मानित किया गया था। उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड (2005), द्रोणाचार्य पुरस्कार (2022), NDTV-प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड (2009), और CNN-IBN इंडियन ऑफ द ईयर (2009) सहित कई सम्मानों से

सम्मानित किया गया था, जो भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

2. पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मेघनाद देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया।



भारतीय मूल के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड मेघनाद जगदीशचंद्र देसाई का 29 जुलाई, 2025 को लंदन में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देसाई को आर्थिक चिंतन, वैश्विक शासन और भारत-UK संबंधों में उनके गहन योगदान के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें एक "प्रतिष्ठित विचारक, लेखक और अर्थशास्त्री" बताया, जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़े रहे।

- जगदीशचंद्र देसाई ने 1963 में पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में अपनी PhD पूरी की, फिर 1965 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) में शामिल हो गए। वे 1983 में पूर्ण प्रोफेसर बने और बाद में 2003 तक प्रोफेसर एमेरिटस के रूप में कार्य किया। उनके स्थायी योगदानों में 1992 में एलएसई में वैश्विक शासन के अध्ययन केंद्र की स्थापना थी। उनके शैक्षणिक कार्य में विकास अर्थशास्त्र, वैश्वीकरण, मार्क्सवादी विश्लेषण और सार्वजनिक

नीति पर 200 से अधिक लेख और 25 से अधिक पुस्तकें शामिल हैं।

- जून 1991 में सेंट क्लेमेंट डेन्स के बैरन देसाई के रूप में ब्रिटिश पीयरज में पदोन्नत होकर, उन्होंने यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लेबर पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। 2020 में, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और यहूदी-विरोधी भावना से निपटने के पार्टी के तरीके पर चिंताओं का हवाला देते हुए क्रॉसबेंच पीयर बन गए। देसाई विकास सहायता, आब्रजन और वैश्वीकरण पर नीतियों को आकार देने में गहराई से शामिल थे।

Key Points:-

(i) 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित, देसाई का योगदान अर्थशास्त्र से आगे बढ़कर कूटनीति और जनसेवा तक फैला हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश संसद के बाहर गांधी स्मारक प्रतिमा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी—जो भारत-ब्रिटेन मैत्री का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी सहित भारत और ब्रिटेन के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की।

(ii) मेघनाद देसाई ने सिद्धांत और व्यवहार का सहज सम्मिश्रण किया—शिक्षा, राजनीति और सार्वजनिक विमर्श के बीच सेतु का काम किया। उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृति पर लेखन जारी रखा।

(iii) उनकी 2022 में प्रकाशित पुस्तक "राजनीतिक अर्थव्यवस्था की गरीबी: अर्थशास्त्र ने गरीबों को कैसे त्याग दिया" ने समावेशी और आलोचनात्मक आर्थिक चिंतन की ओर उनके बौद्धिक विकास को रेखांकित किया। एक मार्गदर्शक के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित, उन्होंने छात्रों और नीति निर्माताओं की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया।

Static GK

SEBI	अध्यक्ष: तुहिन कांता पांडे	मुख्यालय: मुंबई
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
Sashastra Seema Bal (SSB)	महानिदेशक: अमृत मोहन प्रसाद, IPS	मुख्यालय: उदयपुर
United States	राष्ट्रपति: डोनाल्ड ट्रम्प	राजधानी: वाशिंगटन, डी.सी.
Australia	राजधानी: कैनबरा	गवर्नर-जनरल: सैम मोस्टिन
Russia	राजधानी: मास्को	प्रधान मंत्री: मिखाइल मिशुस्टिन
United Arab Emirates	राष्ट्रपति: मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान	प्रधानमंत्री: मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम
All India Football Federation (AIFF)	महासचिव: अनिलकुमार प्रभाकरन	मुख्यालय: फुटबॉल हाउस, द्वारका, दिल्ली
Maharashtra	मुख्यमंत्री: देवेंद्र फडणवीस	राज्यपाल: सी. पी. राधाकृष्णन